and we have taken it up in the important capitals so that those Governments should also impress upon the military rulers of Pakistan the futility and the barbarity of such an action. We have urged other Governments to use their good offices, or to use their influence, to prevent such a tragedy taking place. If I may say, I myself have sent an urgent message to U. Thant yesterday so that he may also use his influence for saving the life of Sheikh Mujibur Rahman.

DR. BHAI MAHAVIR: What about Gromyko?

SARDAR SWARAN SINGH: Mr. Gromyko is strongly in favour of pressing President Yahya Khan and for dissuading him from this type of sham trial.

SHRI ARJUN ARORA: Dr. Bhai Mahavir is disappointed.

DR. BHAI MAHAVIR: It is only rare . . .

MR. CHAIRMAN: Let Mr. Man Singh Varma put the question.

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन्, मिस्टर जान स्टोन हाउस ने जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा है या नही रखा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने संसार के जूरिस्ट्स से अपनी तरफ से पहल कर के इस प्रकार का क्यों नही प्रस्ताव रखा कि उनकी तरफ से इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता कि मुजीब की जान को जो खतरा हो रहा है वह टल सके ? तो आपने अपनी तरफ से पहल क्यो नही की ।

SARDAR SWARAN SINGH: This matter, Sir, has been taken up by the Indian component of the jurists, and to operate successfully in these institutions it is better if the Government is not directly involved and if the Indian jurist members of that Commission themselves take it up, it has greater effect.

FERTILIZER SCHEME

*474. SHRI CHANDRAMOULI JAGARLAMUDI:†
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS/
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री
be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four fertilizer schemes are expected to be completed by the end of 1971; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS/
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री
(SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The fertilizer factories at Durgapur, Cochin and Madras and expansion of the Udyogamandal unit of M|S F.A.C.T. will go into production by the end of 1971. These units will have a total capacity of 516,000 tonnes of Nitrogen and 95,000 tonnes of P.O. 25.

SHRI CHANDRAMOULI JAGARLAMUDI: May I know from the hon. Minister whether it is a fact that in spite of the production of chemical fertiliser going up from year to year, the prices are also going up from year to year and on account of drought condition in many parts of the country, the farmers are not able to purchase their full requirements. Will the Minister prevail upon the Finance Minister to reduce the 10 per cent. *ad valorem* fees levied two years back by the Finance Minister so that the farmers may be able to purchase their full requirements?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chandramouli Jagarlamudi.

SHRI P. C. SETHI: This is actually a suggestion for the Finance Ministry to act.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : फर्टिलाइजर की जो नयी स्कीम आप प्रारम्भ कर रहे हैं उस के पूर्व आपने अपने कट्टी मे फर्टिलाइजर की खपत की दृष्टि से कोई असेसमेंट किया है या नही ? और क्या यह बात सही है कि अपने देश में बड़ी मात्रा मे विदेशो से आयातित फर्टिलाइजर स्टाक में पड़ा हुआ है और उस की खपत नही हो रही है और बाहर से आने वाले फर्टिलाइजर के कारण अपने देश मे जो विदेशी पूंजी है, फारेन एक्सचेंज, उस का बड़ा घाटा हो रहा है और उस के उपरान्त भी आप आयात मे किसी प्रकार की कमी नही कर रहे हैं और आप फर्टिलाइजर मंगाते जा रहे है । तो क्या आप ने कोई असेसमेंट किया है कि कितना फर्टिलाइजर अभी भी अपने यहां स्टाक में पडा हुआ है ?

श्री पी० सी० सेठी : अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर के उत्पादन की दृष्टि से देश में उस की कमी है और इस वजह से वह बाहर से आयात किया जाता है । लेकिन पिछले दो सालो मे इस आयात मे कमी हुई है । दो साल पूर्व करीब 150 करोड रुपये का फर्टिलाइजर देश मे आया था, लेकिन गत वर्ष 74-75 करोड रुपये का आया है और 1973 मे यह जो कमी है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की यह काफी कम हो जायगी । लेकिन सेल्फ सफीशियेन्स का जहां तक ताल्लुक है हम पूर्णतया आत्मनिर्भर तो 1975–76 तक हो सकेंगे ।

श्री मान सिंह वर्मा : अगर कमी है तो उस की खपत भी नहीं हो रही है, यह बात हमारी समझ में नही आती ।

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Will the Government explain as to what is the position of the Tuticorin Fertiliser Plant and what is the cause for the delay in the commissioning of the plant? I would very much like to know whether at least by 1971 or 1972, the entire input will begin to pay dividend to the people of Tamil Nadu and to the people of this country.

SHRI P. C. SETHI: Sir, most of the delay that have taken place in the Tuticorin Fertiliser Plant have been sorted out. I hope it will be able to go on stream at the earliest.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU: I want to know what the stage of progress is of the Ramagundam coal-based fertiliser plant and when it will be commissioned.

SHRI P. C. SETHI: The Ramagundam and Talcher fertiliser projects are coal-based involving new technology. The foreign exchange and the equipment part of it has been tied up, but the actual production of the Ramagundam project will take place sometime in the later half of 1974.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: May I know from the hon. Minister whether it is proposed to have expansion of fertiliser production by having more fertiliser plants in the public sector, or the idea is to have one or two plants more in the private sector? May I also know from the hon. Minister when the new capacity plants at Ambalamedu in Cochin will go into production?

SHRI P. C. SETHI: Fertiliser is in the core sector and, therefore, if any serious proposal for the production of fertiliser in the private sector comes, we would certainly consider it on merits. But as far as the setting up of fertiliser units by the Fertiliser Corporation is concerned, our hands are full at the moment, but looking to the resources available, we would certainly take up new projects as and when it is possible. As far as this particular question of Cochin is concerned, Cochin Phase I work is going on and it is likely that it will be on stream by October, 1971.

SHRI NIREN GHOSH: I would like to know whether the designing manufacture and fabrication of these fertiliser plants referred to in the reply of the hon. Minister have been done by the Planning Division of the Fertiliser Corporation of India, since our information is that it is well equipped for the purpose, or there is foreign collaboration and there has been expenditure of foreign exchange. I would also like to know whether these are based on indigenous raw meterial or, for these units to go on stream, you require import of ammonia or anything like that and spending of foreign exchange, injuring the interests of the country.

SHRI P. C. SETHI: Sir, each plant is based on different feedstock for example, the Durgapur plant is on naphtha; the Cochin plant is also based on napthta; the Madras Fertilizers, which is a joint venture of the Government of India and AMACO, is based on naphtha; Talcher and Ramagundam plants are based on coal. As far as engineering and designing is concerned, the Fertiliser Corporation's engineering division is doing a very good amount of work. But it is true that in new lines, particularly in coal-based fertiliser projects, we are still having equipment and know-how from abroad. Even in the existing plants, the entire 100 per cent designing is not done by the FCI, but they are gradually progressing. Now it is about 66 per cent.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कोरबा उर्वरक योजना की स्वीकृति शासन ने प्रदान कर दी है या नहीं और यहां 2 करोड़ रुपये की लागत का व्यय हो चुका है तो उस योजना की आज क्या स्थिति है ?

श्री पी० सी० सेठी : अध्यक्ष महोदय, कोरबा फर्टिलाइजर्स प्राजेक्ट का जिस समय यह काम प्रारम्भ हो गया था उस समय उसकी वास्तव में स्वीकृति नही हुई थी लेकिन बाद में जब कोल-बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाने का मामला तय हुआ तो प्रिंसिपिल मे सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि तालचेर और रामगुडम के साथ साथ कोरबा को भी लिया जाय-लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से यह तय हुआ था कि तालचेर और रामगुंडम का होने के पश्चात् कोरबा का फेजिंग तय किया जायगा और प्लानिग कमिशन के साथ उसका फेजिंग तय करने को जा रहे हैं और हमे आशा है कि कोरबा प्लांट को भी हम स्थापित कर सकेंगे ।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जो फर्टिलाइजर्स हम बाहर से इम्पोर्ट करते है उसकी इम्पोर्ट प्राइस मे और जिस कीमत पर वह किसानो को दिया जाता है उसमे काफी ज्यादा फर्क है, यानी एक तरह की मुनाफेबाजी होती है उसमे ।

और मन्त्री महोदय ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर मे फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिये आप सोच सकते हैं तो मीठापुर के प्राजेक्ट के बारे मे सोचने मे कितना वक्त लगेगा और क्या यह सच है कि उसमें 2 लाख रुपये रोज के हिसाब से घाटा पड़ रहा है देश को, देश को फारेन एक्सचेज का नुक्सान हो रहा है, यह जो श्री टाटा का कथन था इसमें क्या सच्चाई है और यदि है तो इसके लिये जल्दी निर्णय करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ।

श्री पी० सी० सेठी : अध्यक्ष महोदय, मीठापुर के बारे मे जो भी वर्तमान स्थिति है वह यह है कि उनका एम० आर० टी० पी० सी० का क्लीरयंस हो चुका है लेकिन अभी भी उसमें जो डिले हो रही है वह हमारी वजह से नहीं है, वह इस वजह से है कि सरकार का कहना है कि फासफोरिक एसिड बनाने का प्लांट आपको यहां लगाना पड़ेगा और उनकी तरफ से सजेशन आया है कि फासफोरिक एसिड यहां बनाने के बजाय उसको इम्पोर्ट करना है । फासफोरिक एसिड को यहां बनाने

के बजाय इम्पोर्ट करने में ज्यादा खर्चा होगा और अगर यह चीजें जल्दी तय हो जाय तो उसमें कोई देरी नहीं होगी । कम्पनी ने अभी अपना विस्तृत फाइनान्सिज पैटर्न आदि भी नही दिया है ।

जहां तक बाहर से इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स का ताल्लुक है यह सही है कि हमारे यहां फर्टिलाइजर्स के उत्पादन की कीमत अधिक है और बाहर से जो आता है वह सस्ता है और इसलिये पूलिंग आफ दि प्राइस किया जाता है ।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, कितना फर्क है । किसान को जिस कीमत पर मिलता है और जिस कीमत पर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वह क्या है । यह उन्होंने नहीं बताया ।

श्री सभापति : आप कुछ कह सकते है ।

SHRI P. C. SETHI: Sir, in order to be very exact, I would require notice.

*475. [*The questioner (Shri K. C. Panda) was absent. For answer vide cols. 36-37 infra.*]

†SETTING UP OF POLYESTER FIBRE PLANT IN KERALA

*305. SHRI S. KUMARAN: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS/
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री
be pleased to state:

(a) whether the Kerala State Industrial Development Corporation have requested the Central Government to issue a letter of intent for the setting up of a polyester fibre plant in that State; and

(b) if so, what decision has been taken by the Central Government thereon?

†Transferred from the 2nd August, 1971.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS/
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री
(SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) In the absence of further scope for licensing additional polyester staple fibre capacity in the context of the Fourth Plan targets and the capacity in production, licensed and covered by the letters of intent, the application has been rejected.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. the fact that few modern industries are located in Kerala, will the Government reconsider this question sympathetically (*Interruptions*).

SHRI P. C. SETHI: No, Sir, it is not discrimination. As a matter of fact the estimated demand by 1973-74 for polyester fibre including filament yarn is about 22,000 tons. Already the filament yarn is 6,000 tons. Therefore, the actual requirement of fibre is 16,000 tons. In view of the fact that the targets are only indicative and this being not in the core sector, the Government has licensed about 30,000 tons and therefore, there is hardly any possibility unless the Kerala State Government takes the responsibility of exporting 60 per cent of the product because now we will have to give the licence on the basis of imported DMT and therefore, unless they give a guarantee of export it would not be possible.

SHRI BALACHANDRA MENON: I should like to know when the application was made to the Government by the KSIDC. I should also like to know whether the Government will allow the setting up of this factory if the Kerala Government agrees to export.

SHRI P. C. SETHI: As I have said, if they agree to export 60 per cent of the product, certainly we would consider it. As far as the question of the date of application of this licence is